leased out to the Maharashtra State Electricity Board. This is a very extraordinary situation which we are not able to understand. I am given to understand that the monthly expenditure is of the order of Rs. 840 croress. They are recovering about Rs. 40 crores and the rest of the money they just don't have. That means the amount of money that they are going to get even from the private parties is going to be spent as revenue expenditure. If the money which they are getting is going to be spent as revenue expenditure for payment of regular monthly bills to either the employees or others, then, of course, it would be a very extraordinary situation which needs to be looked into by the Government of India. Mightbe, at some stage, the hon. Members can ask, "After all, it is a State subject. How can you raise it here?"

I would like to mention another factor and that is about one multi-national company called "Enron". They have also completed their erection and they are going to start generation of power and they have thereatened that of the cheaper electricity which is being produced by TATA and BASES, almost 8 million units will have to be given up so that they have to purchase only from Enron. As regards this Enron project, a counter-guarantee was given by the Government of India. Now the new Government seems to have made an announcement—I do not know about it—on the very first day that the State Government have been empowered to invite foreign investment on electricity generation to a limit of Rs. 1,500 crores. They can enter into negotiations and finalise the deals up to that amount. They need not come to the Government of India at all. I doubt whether they will be able to do anything unless the Government of India gives a counter-guarantee. These are all matters which definitely need to be gone into. The employees have given notice that if these sets are going to be sold to private people or if they are going to be given on lease, they will go on strike. If there is going to be a State-wise strike and if there is total mismanagement as is being brought to our notice, I have no doubt in mind that there will be a difficult situation. We have been resisting counter guarantee and insisting that counter-guarantee should not be given to the multinational companies. Even the World Bank in its report has stated that they should face the music themselves. Why should the Government of India give a counter-guarantee for such a proposal? But in spite of all that, the counter-guarantees have been given and that is why there is a very alarming, a very disturbing situation, in Maharashtra. I have no doubt in my mind that this is going to be a first-class crisis in the electricity sector in Maharashtra State, and the Government of India, if the counter-guarantee is invoked, has to shell out the money to the multinational companies. So, this is the situtation which I would like the Prime Minister to clarify. Maybe, I am making this kind of a statement on the basis of a report which I have read. I would like to have the exact position. I would like to know what the prevailing situation in that area is and what is being proposed to be done in order to see that such kind of mismanagement is stopped and the Government of India is not asked to make good the losses, which the multinational companies are going to incur, by way of invoking the counter-guarantee. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: Now Motion of Thanks on the President's Address, Shri Sunder Singh Bhandari.

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (राजस्थान) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :-

"राष्ट्रपति ने 25 मार्च, 1998 को ससंद की दोनों सभाओं की सम्मिलित बैठक में कृपया जो अभिभाषण दिया है ,उसके लिए राज्यसभा के सदस्य, जो सभा के वर्तमान सत्र में उपस्थित हैं, राष्ट्रपति के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं ।"

सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी का यह अभिभाषण इस समय 12वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न होने के बाद हुआ है । दो साल पहले भी चुनाव हुए थे । 11वीं लोकसभा के और उस समय भी मेरी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सहयोगी दलों के साथ चुनाव लड़ा था और सबसे बड़े दल के रूप में उभरकर सामने आई थी परन्तु फिर भी सरकार बनाना संभव नहीं हुआ । दो और परीक्षण हुए सरकार बनाने के और सरकार चलाने के परन्तु 2 साल के बाद ही फिर से नए चुनाव कराने की नौबत आ गई । इस बार उस कमी को दूर करने का प्रयत्न कुछ हद तक हुआ है । चुनाव के पूर्व अनेक दलों के साथ गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और परिणामस्वरूप भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में इस बार भी जीतकर आई । और सहयोगी दलों के साथ भी सबसे बड़ा गठबंधन उसका बना ।

परन्तु फिर भी स्थिति स्पष्ट नहीं थी और जब राष्ट्रपति महोदय ने हमारे नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा, तो उन्होंने साफ कहा कि मेरे पास स्पष्ट बहुमत तो नहीं है लेकिन फिर भी हम सरकार बनाकर अपना बहुमत सिद्ध करने का प्रयत्न कर सकते हैं । राष्ट्रपति महोदय ने अन्य दलों के नेताओं से भी परामर्श किया और अन्त में वे इस नतीजे पर पहुंचे कि वाजपेयी जी को प्रधान मंत्री की शपथ दिलाकर सरकार बनाने का अवसर दिया जाए और दस दिन के अदंर उन्होंने विश्वास मत प्राप्त करने के लिए उन्हें निर्देशित किया। आज जब मैं आपके समाने खड़ा हूं तो । यह घटना पूरी हो चुकी है और गत शनिवार को वर्तमान सरकार को विश्वास का मत प्राप्त हो गया है और सरकार बनाने की प्रारम्भिक भूमिकाएं सम्पन्न हो चुकी हैं।

सवाल खड़ा होता है कि ऐसी परिस्थिति में जब सदन दोनों तरफ से पूरा आधा-आधा बंटा हुआ हो, क्या व्यवस्था की जाएं? यह बात तो सच है कि वकेंबल मजारिटी । चाहिए और बिना वकेंबल मजा रिटी के कोई भी सरकार टिक नहीं सकती । लेकिन जिस तरीके से सदन का गठन हुआ है उसमें वकिंग मजारिटी यह हमेशा संदिग्ध रहने की सम्भावना है और इस आधार पर काम करने की एक ऐसी पद्धति हमें इवॉल्व करनी पडेगी जिसमें राष्ट्रीय महत्व के मारे प्रश्र जो देश के साथ सम्बन्ध रखते हैं, आम नागरिक के साथ सम्बन्ध रखते हैं, उनको हल करने केलिए उसके संबंध में पार्लियामेंट सैक्शन प्राप्त करने केलिए कोई तरीका हम बनाएं उस पद्धति को स्वीकार करे और उस आधार पर सरकार को दीर्घकाल के लिए चलने का अवसर दें।

भारतीय जनता पार्टी ने अपने मोनिफेस्टो पर चुनाव लड़ा था। जिनके साथ चुनाव गंठबधन था उन्होंने भी अपने अपने मेनिफेस्टो पर चुनाव लड़ा और चुनाव में जब जीतकर आए और सरकार बनाने की सम्भावनाएं हुई तो सभी दलों ने इक्ट्ठे बैठकर आज की परिस्थिति में जिस तरीके से सरकार बनी है उसके लिए एक नेशनल एजेंडा बनाया । स्वाभाविक बात है कि अपनर-अपनी पार्टियों की कुछ चीजें छोड़कर यह नेशनल एजेंडा बना है । पार्टियों के मेनिफेस्टो अपनी जगह पर कायम हैं। यह सरकार बंधी हुई है एक नेशनल एजेंडा से और जैसा कि प्रधान मंत्री ने परसों आश्वास्त किया कि यह सरकार नेशनल एजेंडा तक ही अपनी कारगुजरारी सीमित करने के लिए वचनबद्ध है और इस कारण से यह कहना है कि बी.जे.पी. का दिन हिडन एजेंडा है, नेशनल एजेंडा अपनी जगह है। यह सरकार कुछ और बातें लेकर जो आज बोलना नहीं चाहती काम करना चाहती है, मैं अपनी सरकार की ओर से यही आश्वाश्त कर सकता हूं कि जब सभी गठन जोड़ वाली पार्टियों ने मिलकर एक रिटन नेशनल एजेंडा स्वीकार किया है तो यह गवर्नमेंट का कमिटमेंट उस नेशनल एजेंडा तक सीमित है और मुझे विश्वास है कि यह सरकार उस नेशनल एजेंडा के आधार पर आम नागरिक की मूलभूत आवश्यकताएं देश की एकता, देश की सुरक्षा और आर्थिक उन्नति के लिए निश्चित रूप से इस देश की सेवा करने में सक्षम होगी । सभापति महोदय, मैं आर.एस. एस. का सदस्य हूं और आर.एस.एस. का सदस्य मैं उस समय से हूं जब मैं जनता पार्टी में शामिल हुआ था, बचपन से उसका सदस्य हूं, आज 50-55 साल हो गए । इस कारण से संघ के सस्कांर मेरे जीवन में है। आज संघ के संस्कारित व्यक्ति देश और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार कर रहे हैं । कोई शिक्षा के क्षेत्र में है, कोई उद्योग के क्षेत्र में है, कोई वकील है कोई डॉक्टर है, कोई पोलिटिशियन है, कोई समाज-सुधारक है और ये सब एक ज्वाइंट फैमिली की तरह है। ज्वांइट-फैमिली मे हम सब एक संस्कार से प्रभावित है परन्तु अपने-अपने क्षेत्रों में अन्य लोगों को साथ लेकर हम अपने-अपने क्षेत्रों में अन्य लोगों को साथ लेकर हम अपने क्षेत्र के लिए जो काम देश सेवा का और इस देश के सांस्कृतिक पुनरूथान करना चाहते हैं, उसमें किसी एक का दूसरे के साथ दखल नहीं है । आर.एस.एस. अपनी जगह पर है, विश्च हिंदू परिषद और ऐसे अनेकों संगठन है जो आज देश के विभिन्न क्षेत्रों में आज से नहीं, 25 साल से 30 साल से, 40